बोल कर बंद किया जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माँग करूंगा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण पर अपनी एक पॉलिसी लानी चाहिए कि जो विस्थापित लोग हैं, जब तक उनके लिए एक सटीक रिहैबिलिटेशन पैकेज तैयार न हो, जब तक उनकी रोज़मर्रा की रोटी कमाने की व्यवस्था तैयार न हो, तब तक जमीन का अधिग्रहण न हो। इसके लिए उसको कोशिश करनी चाहिए और इसकी रूपरेखा वह सदन के सामने लाये और राज्यों को कहे। हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने खास कर संथाल परगना के ट्राइबल्स और आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए प्रावधान कर रखा है। उस प्रावधान को ताक पर रखकर उनसे जबरन जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने साथी, जिन्होंने यह आवाज़ उठाई, उनका समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई हो।

SHRI ABANI ROY (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter issued by Shri S.S. Ahluwalia. वहां के जो 75 प्रतिशत आदिवासी हैं, कम से कम उनसे जमीन न ली जाए।

SHRI RANJIT PRASAD (Bihar): Sir, I also associate with the matter raised by Shri S.S. Ahluwalia.

The VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Ajay Singh Chautala; not present. Sardar Tarlochan Singhji.

Farmers' agitation for substantial reduction in the prices of diesel and petrol

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा): थैंक यू, वाइस चेयरमैन साहब। पिछले दिनों सरकार ने डीज़ल और पैट्रोल की प्राइसेस कुछ कम की हैं। ऐसा लगा है कि जैसे आटे में नमक के बराबर की है। वाइस चेयरमैन साहब, मैं आज यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि किसानों को डीज़ल की जरूरत है। सरकार की जो भी पॉलिसी आती है, कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, उसमें सबसे कम किसान को मिलता है। रेसेसन को दूर करने के लिए सरकार ने अभी हजारों करोड़ की नयी स्कीमें निकाली हैं लेकिन एक भी ऐसी स्कीम नहीं है जो हम कह सकें कि फार्मर्स के लिए है। आजकल हरियाणा और पंजाब में wheat की sowing हुई है। हरियाणा में बिजली है ही नहीं। किसानों को डीजल चाहिए। विदेशों में जो डीज़ल और पेट्रोल की प्राइस थी, वह 147 डॉलर प्रति बैरल थी, वह आज 43 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। इस प्रकार इसमें 67 परसेंट की कमी हुई है लेकिन हमें केवल दो रुपया दिया गया है। यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि विदेशों में प्राइस जब इतनी कम हुई तो इंडिया में इसके बराबर की क्यों नहीं की गई और न ही मिट्टी के तेल और गैस के दामों में कोई कमी की गई। इसके अलावा, अभी सरकार ने चार परसेंट एक्साइज ड्यूटी माफ की, लेकिन यह डीजल पर लागू नहीं है, बाकी सब पर है। यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि किसानों का जब कोई इश्यू आता है तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। परसों ही करीबन पांच हजार हरियाणा के किसान इकट्ठे हुए, सब ने एक ही बात कही कि डीजल की प्राइस कम की जाए। हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको लीड किया। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनको कहूंगा कि यह नॉर्थ इंडिया, हरियाणा और पंजाब सारे देश को wheat और चावल देता है, इनके लिए स्पेशल पैकेज प्रोग्राम लाया जाए और खास कर जो डीजल और केरोसीन ऑयल की प्राइस है, वह कम की जाए ताकि इस सीज़न में उनको यह इंसेंटिव मिले और हम ज्यादा प्रोडक्शन दें। देश में किसान का जो रोल है, सरकार उसको रेकग्नाइज़ करे और इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। थैंक यू, सर।